विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थान में स्कूल भवनों का ढहना- ''आओ फूलों के जनाजे देखो''

आपने हमने जनाजो पर फूल चढ़ाते हुए तो बहुत देखे हैं, मगर खुद फूलों के जनाजे देखे तो दिल दहल गया। सात बच्चे जर्जर स्कूल की क्लास रूम मे दब कर मर गये और कोई हल्ला ना हुआ। सन्नाटा पसरा रहा है चारों और। उनके लिए ना कोई अगरबत्तियां जलाई गई ना ही कोई जुलूस निकाले गये। वे बच्चे गरीब थे इसलिये सरकार ने उनकी हैसियत देख कर उनकी जान की कीमत दस लाख लगाई गई। शिक्षा मंत्री घूम आये, दोषी को सजा देने का आश्वासन देकर। इतना बड़ा हादसा और कोई इस्तीफा नहीं, कोई दोषी नहीं। संवेदनायें मर चुकी हैं, हम स्वार्थी हो चले हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिये था मगर ये सम्भव नहीं था क्योंकि मृतको में हमारा कोई नहीं था।

छोटे-छोटे मासूम बच्चों का जब सामुहिक संस्कार हुआ तो मोक्ष धाम की धरती भी कांप गई। अधिकांश सरकारी स्कूल कांपती स्थिति मे है। एक सर्वे मे 90% सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल मे पढ़ते है। मतलब इन स्कूलों में उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे जो यहां पढ़ा कर सरकारी शिक्षक बने बैठे हैं। सात बच्चों की दर्दनाक मृत्यु से मन बहुत विचलित और असहाय है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। 28 जुलाई 2025 को जैसलमेर के हाबूर (पूनमनगर) में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार का पत्थर गिरने से छुट्टी के समय एक मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, और एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह खंभा पहले से ही जर्जर हालत में था, और इसकी मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा स्थानीय सत्ता रूढ़ पार्टी के विधायक छोटूसिंह भाटी के पैतृक गांव में हुआ है जो सरकार की उदासीनता को और भी शर्मनाक बनाता है। इससे ठीक एक दिन पहले, 27 जुलाई 2025 को जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। सौभाग्य से, उस समय कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि राजस्थान के स्कूलों की स्थिति कितनी भयावह है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पीपलोदी गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 अन्य के घायल होने की दिल दहला देने वाली घटना ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख ही दिया है। यह हादसा सुबह 7:45 बजे हुआ, जब बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की इमारत 78 साल पुरानी थी, और स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी जर्जर हालत की शिकायत की थी। बच्चों ने हादसे से पहले छत से कंकड़ गिरने की बात शिक्षकों को बताई थी, लेकिन शिक्षकों ने इसे नजरअंदाज कर बच्चों को डांटकर चुप करा दिया। इस हादसे में मरने वाले आठ बच्चे 8 से 11 साल की उम्र के थे, और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर घ्ण्ळ में भर्ती हैं। झालावाड़ हादसे के ठीक एक दिन बाद, नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में खरियावास के सरकारी प्राथमिक स्कूल की छत अचानक ढह गई। सौभाग्य से, इस समय कोई बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि स्कूल भवनों की जर्जरता पूरे राज्य में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि अगर बच्चे मौजूद होते, तो कौन जिम्मेदार होता? राज्य के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने हादसे का नैतिक दायित्व लेते हुए कहा कि सरकार की प्रक्रिया से ही भवनों के मरम्मत का पैसा भेजा जाएगा। इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन हम हादसों का इन्तजार क्यों करते हैं। सरकार को यह सब समय से पहले क्यों नहीं सूझता। राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। 2023 में बीकानेर जिले के एक सरकारी स्कूल में छत का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। स्कूल की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2022 में उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की, लेकिन दो साल बाद भी वह स्कूल जर्जर हालत में है। 2021 में जयपुर के एक सरकारी स्कूल में बारिश के कारण छत से पानी रिसने की वजह से दीवार ढह गई थी, जिसमें एक शिक्षक और एक बच्चा घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट का वादा किया था, लेकिन यह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने हर बार जांच कमेटियां गठित कीं, मुआवजे की घोषणाएं कीं, और स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित करने का दावा किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश वादे हवा-हवाई साबित हुए। 2023 में बीकानेर हादसे के बाद स्वीकृत राशि का केवल 30% ही उपयोग हुआ, और बाकी राशि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ गई। उदयपुर हादसे के बाद घोषित 50 लाख रुपये का उपयोग आज तक नहीं हुआ, और वह स्कूल आज भी बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है।

इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। शिक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2,710 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, और 2,256 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि समस्या व्यापक और गंभीर है, हकीकत में यह आंकड़ा भी कागजी है वास्तविकता इससे अधिक खराब है। फिर भी, सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। झालावाड़ हादसे में यह सामने आया कि स्कूल की इमारत को जर्जर भवनों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। यह न केवल लापरवाही है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। अगर शिक्षा विभाग को इस स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं थी, तो उनकी सूची कितनी विश्वसनीय है? क्या अन्य स्कूल, जो इस सूची में नहीं हैं, वाकई सुरक्षित हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ हादसे को 'कांग्रेस का पाप' बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अगर पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी तो उससे पहले भाजपा की सरकार रही थी अत: यह बयान न केवल अनुचित है, बल्कि उस मानसिकता को दर्शाता है जो समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक दोषारोपण को प्राथमिकता देती है। क्या सात बच्चों की मौत और जैसलमेर में एक मासूम छात्रा की जान जाने के बाद भी सरकार का 'चरणबद्ध' भवनों की मरम्मत का दृष्टिकोण उचित है? क्या मासूमों की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि सरकार भवनों धीरे-धीरे ठीक करने की बात करे? जैसलमेर हादसे में, जहां सरकार के अपने विधायक के अपने गांव में ही हादसा हुआ, सरकार की चुप्पी और भी अखरने वाली है। पिछले साल स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और इस साल यह राशि बढ़ाकर 175 करोड़ रुपये की गई। लेकिन यह राशि भी अपर्याप्त है, क्योंकि 2,710 स्कूलों की मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो अभी भी वित्त विभाग में मंजूरी के लिए अटकी पड़ी है। यह प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार का एक जीवन्त उदाहरण है, जो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है।

झालावाड़ हादसे के बाद पांच शिक्षकों और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि बच्चों की शिकायतों को नजरअंदाज करना और उन्हें डांटकर चुप कराना शिक्षकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी। लेकिन क्या यह हादसा केवल शिक्षकों की गलती का नतीजा था? शिक्षकों ने कई बार स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों से मरम्मत की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। शिक्षकों को निलंबित करना एक आसान रास्ता है, जो सरकार को अपनी जवाबदेही से बचने का मौका देता है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं, न ही उनके पास स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट या अधिकार हैं। फिर उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है? शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? जैसलमेर और जोधपुर हादसों में भी यही पैटर्न देखने को मिला, जहां सरकार ने तुरंत शिक्षकों पर कार्रवाई की, लेकिन असल जिम्मेदारों-प्रशासन और PWD-को छूने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह साफ है कि सरकार शिक्षकों को बलि का बकरा बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हां अगर यही हादसा किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाता तो पूरा प्रशासनिक अमला स्कूल संचालक के खिलाफ सक्रिय हो जाता और अब तक उसे सलाखों के पीछे धकेल चुका होता और ताबड़तोड़ आदेशों और उपदेशों की बाड़ आ जाती।

राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम हैं। एक जगह सही कहा गया है कि ''जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार'' भारत की कटु सच्चाई है। झालावाड़ हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी राज्यों को स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता भर साबित होगी, अगर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई है। जैसलमेर हादसे में भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन क्या यह मुआवजा उन मासूमों की जान वापस ला सकता है? एक पिता, छोटूलाल, ने अपने दोनों बच्चों-कान्हा और मीना-को झालावाड़ हादसे में खो दिया। एक आठ साल का बच्चा, कार्तिक, अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। अब उसकी बहनें किसे राखी बांधेंगी? जैसलमेर में मृत छात्रा के परिवार का दर्द भी कम नहीं है। ये बच्चे गरीब और बहुजन समाज से थे, जो निजी स्कूलों की मोटी फीस नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल उनकी एकमात्र उम्मीद थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस उम्मीद को भी धोखा दिया। जैसलमेर में यह तथ्य और भी दुखद है कि हादसा विधायक के अपने गांव में हुआ, फिर भी सरकार और प्रशासन खामोश रहे।

यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हैं, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, और उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूल खराब हालत में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संकट है, जिसे नजरअंदाज करना अब असंभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की। यह कदम सराहनीय है, लेकिन यहां खानापूर्ति होकर न रह जाए? जैसलमेर और जोधपुर, झालावाड़ के हादसों के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या कार्रवाई नहीं देखी गई। पहले भी ऐसी कमेटियां बनती रही हैं, और नतीजा शून्य रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल भवनों की स्थिति पर स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है उधर केंद्र सरकार ने भी देश भर के स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो 2021 के सुरक्षा दिशा-निर्देशों और 2016 के आपदा प्रबंधन निर्देशों के अनुसार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों का पालन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ऑडिट को गंभीरता से लेंगे, या यह भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तत्काल सुरक्षा ऑडिट करना होगा, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों की जांच की जाए और जर्जर भवनों को तुरंत बंद कर बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ाया जाए। मरम्मत के लिए राशि को तुरंत जारी किया जाए, और इसके उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए इतना ही नहीं भवन मरम्मत के लिए आपात निधी का भी प्रथक से प्रावधान हो जिसे जिला कलेक्टर स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हों। मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए। केवल शिक्षकों को दोषी ठहराने के बजाय जिला प्रशासन, और PWD के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय पंचायतों को भवन सुरक्षा और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जर्जर स्कूलों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर आधुनिक और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जाए। स्कूलों में नियमित रूप से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाएं।

अगर अब भी सरकार नहीं जागी, तो अगली दीवार कहीं और गिरेगी, और तब शायद सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

गोस्वामी तुलसीदास : एक संत कवि के सामाजिक सरोकार

राजेश्वर सिंह

गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भारत की भक्ति काव्य परंपरा की सगुण शाखा के शीर्षस्थ कवि हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस, कवितावली , दोहावली सहित अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया जिसमें मानस की प्रतिष्ठा एक धर्म ग्रंथ के रूप में व एक कालजयी साहित्यिक कृति के रूप में आज तक बरकरार है और भविष्य में भी बनी रहेगी। मानस की अपार लोकप्रियता का आधार केवल धार्मिक नहीं है। इसमें व गोस्वामी जी की अन्य कृतियों में न केवल तात्कालिक परिवेश व जनजीवन के दु:ख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा और वेदना का सजीव चित्रण है वरन इनमें इसको सहन व शमन करने के लिए तमाम उपायों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें राम की भक्ति सर्व प्रमुख है। यह तुलसी के पालन पोषण, अध्ययन, चिंतन तथा समकालीन परिवेश से अर्जित संस्कार से उद्भूत समाधान है।

किंतु तुलसी यहीं पर नहीं रुकते। वह अकाल, दुर्भिक्ष, व्याधि व क्षुधाकुलता का वर्णन तो करते ही हैं पर उसके साथ ही राम राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य तथा जनहितकामी शासन तंत्र की संकल्पना भी प्रस्तुत करते हैं जो कि तत्कालीन शासकों पर एक अप्रत्यक्ष प्रहार की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। तुलसी जब कहते हैं कि ''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवसि नरक अधिकारी'' तो उनकी निर्भीकता व स्पष्टवादिता की कल्पना करके दंग रह जाना पड़ता है।

तुलसी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति की तलाश में किसी पर्वत की खोह या कंदरा में ध्यान साधना करने वाले संत नहीं थे। वह आम जनता के जीवन के दु:ख व कष्ट से जुड़े हुए संत कवि थे। कवितावली में जब वह कहते हैं कि किसान के लिए खेती बाड़ी नहीं है, भिखारी के लिए भीख नहीं है, व्यवसायी के लिए वाणिज्य नहीं है और नौकर के लिए नौकरी नहीं है। जीविकाविहीन लोग एक-दूसरे से चिंतित होकर पूछ रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें, तो बरबस ही आज के हिंदुस्तान का चित्र आंखों के समक्ष समुपस्थित हो जाता है जहाँ स्थितियां पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल हो गई हैं।

जन सामान्य के सुख-दु:ख से तुलसी के अभिन्न जुड़ाव का कारण यह था कि उनका स्वयं का बचपन नारकीय अभाव, बुभुक्षा और भिक्षावृत्ति पर अवलंबित था। इसका साकार वर्णन वह कवितावली में करते हैं जब वे कहते हैं कि मैं धूप से बिलबिलाते हुए एक द्वार से दूसरे द्वार पर भिक्षाटन किया करता था व भिक्षा में मिले हुए अन्न के दानों को ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चार फल समझता था। गरीबी व अभाव के इस स्वअर्जित व स्वानुभूत अनुभव के कारण ही वह आम जन के दैनिक जीवन की पीड़ा और अभाव को इतनी गहराई से अभिव्यक्त कर पाते थे।

विद्याध्ययन की समाप्ति के उपरांत जब उन्होंने काशी को अपनी कर्म भूमि बनाया तो वहां के पंडितों ने तुलसी को ब्राह्मण मानने से ही इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप तुलसी की लेखनी से इन कालजयी पंक्तियों का प्रणयन हुआ जो कहती हैं कि चाहे तुम लोग मुझे धूर्त कहो या अवधूत, राजपूत कहो या जुलाहा, मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है और न किसी की जाति बिगाड़नी है। तुलसी तो राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसे अन्य लोग चाहे जो कहें, वह मांग कर खाता है और मस्जिद में सोता है, उसे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है।

एक तरफ प्रचंड दैन्य और दूसरी तरफ प्रखर आत्मविश्वास, यह तुलसी के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषता है। दीनता आई है, घोर अभावग्रस्त बचपन और जाति आधारित अपमान से और आत्मविश्वास आया है राम की भक्ति से। वह कहते हैं कि हम तो जन्म से ही जहर पीने वाले हैं जो लोगों की व्यंग और कटुक्तियाँ सुनते और सहते आए हैं। हम इसका लेश मात्र भी बुरा नहीं मानते क्योंकि अपना मूल्य व महत्व हम जानते हैं। उत्कट संघर्ष, आत्यन्तिक समर्पण व अद्भुत सृजनात्मकता पर आधारित अदम्य आत्मसम्मान की ऐसी प्रभावी अभिव्यक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसी पर वर्ण व्यवस्था का संपोषक व स्त्री विरोधी होने के आक्षेप लगाए जाते हैं, किंतु यह आक्षेप लगाने वाले भूल जाते हैं कि आज के हिंदुस्तान में भी श्रमजीवी जातियों व स्त्रियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति दयनीय ही है। आज भी उन्हें सामाजिक व्यवस्था में समानता पर आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है।

यह सही है कि तुलसी अपने समय, परिवेश, पालन पोषण व संस्कार की सीमाओं का पूर्णरूपेण अतिक्रमण नहीं कर पाए लेकिन जब तुलसी के राम निषादराज गुह से बराबरी के आधार पर मित्रता करते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं, महापराक्रमी व बलशाली रावण का मुकाबला करने के लिए वनवासियों की मदद लेते हैं, तब इन सीमाओं का प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष अतिक्रमण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नारी की स्थिति पर तुलसी की उक्ति ''कत विधि सृजी नारी जग माहीं,पराधीन सुख सपनेहँ नाहीं'' उक्त संपूर्ण समुदाय के प्रति तुलसी की मार्मिक अनुभूति का असंदिग्ध प्रमाण है।तुलसी के राम राज्य में स्वस्थ, संपन्न व सुखी नागरिकों की कल्पना तो है ही, ऐसे स्नानघाटों का विवरण भी है जहां चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। उनके राम एक सामंती राज्य के मुखिया हैं किंतु वह अपनी प्रजा को अभय दान देते हुए उन्हें अपने किसी भी अनीतिपूर्ण कार्य की बेहिचक आलोचना का अधिकार प्रदान करते हैं जो आज के तथाकथित लोकतांत्रिक राज्य में भी अकल्पनीय व असंभव है। तुलसी की भक्ति एक ऐसा धरातल है जो वर्ण, जाति, लिंग व सामाजिक स्थिति की तमाम विषमताओं का अतिक्रमण करती है और सबको मुक्ति का समान अधिकार प्रदान करती है।

तुलसी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग खुद से बढ़कर सीताराम को मानते हैं, उनके पांव का जूता बनाने के लिए तुलसी अपने तन का चमड़ा भी समर्पित करने को तैयार हैं और यह सीताराम और कहीं नहीं है वरन वे संपूर्ण जगत के समस्त नर नारियों में ही समाहित हैं, जिन्हें तुलसी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार तुलसी का काव्य आम जनजीवन की पीड़ा का गहराई से अनुभव करने वाला, जाति भेद, वर्गभेद व लिंग भेद के प्रति गहन आक्रोश की अभिव्यक्ति का तथा स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व पर आधारित आदर्श राज्य और समाज की संकल्पना का काव्य है। यह भारतीय जन की आशा, आकांक्षा व अपेक्षा का शाश्वत घोषणा पत्र है।

-राजेश्वर सिंह,
आईएएस (सेवानिवृत्त)

झालावाड़ हादसे के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये बजट की स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीपलोद स्कूल हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया

हिमांशु सिंह

हादसा होना बेहद दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दोषियों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हादसों से सबक लेकर भविष्य के लिए बेहतर चौकसी और समन्वय ही हादसे में मृत बच्चों को श्रृद्धांजलि होगी। झालावाड़ के पीपलोद स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी दिन शाम को साढ़े छह बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रेसपोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम बस एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जींस में है। इसमें नेतृत्व सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अथॉरिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में है और वह है।

आमजन के साथ तादात्म्य कर उनकी आंकांक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकांक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करे। सभी जिलों से जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों व अन्य भवनों की सूची 2 घंटे में तैयार होना, तत्काल एस्टीमेट बनाना, इसे अप्रूव करवाना, वित्त एवं अन्य विभागों से आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति करवा कर कई प्रकार की स्वीकृतियां करवाना इसी सक्षम और जन उन्मुखी नेतृत्व का परिणाम है।

■ प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए

गौरतलब है कि अजमेर जिले के 185, अलवर के 6, ब्यावर के 109, बारां के 48, भीलवाड़ा के 232, बीकानेर के 55, बूंदी के 22, चित्तौड़गढ़ के 51, दौसा के 153, डीडवाना-कुचामन के 260, धौलपुर के 5, डूंगरपुर के 16, हनुमानगढ़ के 168, जयपुर के 123, जालौर के 132, झालावाड़ के 118, झुंझुनूं के 289, करौली के 101, खैरथल-तिजारा के 24, कोटा के 37, कोटपुतली-बहरोड़ के 24, नागौर के 186, पाली के 141, राजसमंद के 81, सलूंबर के 198, सवाई माधोपुर के 120, श्रीगंगानगर के 114, सिरोही के 317, टोंक के 129 व उदयपुर के 344 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है।

ठीक इसी तरह सीएम शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 1936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से भवन मरम्मत, छत एवं दीवारों का सुदृढ़ीकरण, फर्श और शौचालय सुधार, बिजली एवं जल सुविधाओं का विकास, खेल मैदान का सुधार तथा कक्षाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

इसके तहत अजमेर में 47, अलवर में 48, बालोतरा में 44, बांसवाड़ा में 57, बारां में 36, बाड़मेर में 60, ब्यवार में 29, भरतपुर में 35, भीलवाड़ा में 118, बीकानेर में 56, बूंदी में 35, चित्तौडगढ में 42, चूरू में 27, दौसा में 42, डीग में 30, धौलपुर में 59, डीडवानामेंकुचामन में 59, डूंगरपुर में 46, गंगानगर में 37, हनुमानगढ़ में 31, जयपुर में 174, जैसलमेर में 31, जालौर में 50, झालावाड़ में 51, झुंझुनूं में 44, जोधपुर में 72, करौली में 41, खैरथल-तिजारा में 11, कोटा में 76, कोटपुतली में 28, नागौर में 49, पाली में 62, फलोदी में 19, प्रतापगढ़ में 33, राजसमंद में 33, सलूंबर में 16, सवाई माधोपुर में 39, सीकर में 42, सिरोही में 27, टोंक में 32 व उदयपुर में 68 विद्यालयों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है।

दरअसल हम हमेशा इतिहास से सीखते आए हैं। पूरी मानव सभ्यता का क्रमिक विकास इसी गुण पर टिका हुआ है। कोई भी सिस्टम 100 फीसदी सुरक्षित नहीं होता लेकिन प्रयास हमेशा 100 फीसदी होने चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार यही कार्य कर रही है ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मानवीय करूणा, लचीलापन और नैतिकता की नींव पर खड़ी भजनलाल सरकार हमें आश्वस्त करती है कि हम ऐसे हादसों को परास्त कर आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देंगे, उन्हें हमसे बेहतर नागरिक के रूप में विकसित करेंगे। बतौर सजग और जागरुक नागरिक, आओ ! हम भी अपने आसपास के वातावरण, भवन, घरों की स्थिति के लिए जागरुक बनें और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होने से रोकें।

हिमांशु सिंह राजस्थान सरकार में पीआरओ हैं और वर्तमान में झुंझुनू में कार्यरत हैं।

राशिफल गुरूवार 31 जुलाई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:42 तक, साध्य योग रात्रि 4:32 तक, गर करण दिन 3:50 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:15 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा रात्रि 4:27 से आरम्भ होगी। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती है। आज शीतला सप्तमी (सिन्ध) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:34 तक, चर 10:53 से 12:33 तक, लाभ-अमृत 12:33 से 3:52 तक, शुभ 5:32 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:54, सूर्यास्त 7:12

मेष

स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बना मन का भय समाप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

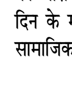

व्यावसायिक आर्थिक मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मिथुन

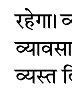

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क

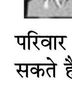

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग और व्यक्तिगत प्रयासों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। धन हानि का भय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में ध्यान देना ठीक रहेगा।

कन्या

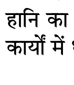

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला

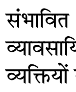

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

वृश्चिक

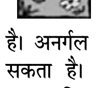

आर्थिक/वित्तीय मामलों दिन के मध्यान्ह पूर्व करने का प्रयास करें। मध्यान्ह पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। घर-गृहस्थी के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

धनु

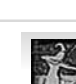

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर

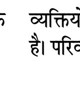

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कुंभ

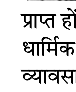

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी।

मीन

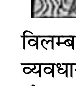

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।